CC MM YY KK

RNI. No. MAHHIN-2014/55445 Postal Reg.No. NPCity/437/2023-2025 www.kendriyamanavadhikar.com

केन्द्रीय सम्माननीय जीवन समान अधिकार दैनिक

मानवाधिकार

| नागपुर. शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 | वर्ष - 13 | अंक - 157 | पृष्ठ - 4 | मुल्य - 2 रु. | संपादक : मिलिंद दहिवले

दैनिक केन्द्रीय मानवाधिकार
हिन्दी समाचारपत्र के लिए चाहिए
पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, फोटोग्राफर, काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, मार्केटिंग विभाग इंचार्ज, न्यूज एंकर, वीडियो एडिटर, टेलीकॉलर, इवेन्ट मैनेजर
M/F उमेदवार शीघ्र संपर्क करे
- मुख्य कार्यालय -
प्लॉट नं. 386, चंदन नगर, नागपुर-440 024
संपर्क - 9552011005

न्यूज गैलरी

पुरुषों ने भी ले लिए लाडकी बहिन योजना के पैसे - अदिति तटकरे

मुंबई – महाराष्ट्र में पुरुषों ने भी लाडकी बहिन योजना के पैसे ले लिए हैं। इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है और मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि ऐसे पुरुषों पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना का लाभ पुरुषों ने भी उठा लिया है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद सियासी बवाल जारी है। जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में करीब 14000 पुरुषों ने लाडकी बहिन योजना का लाभ उठा लिया है, जो केवल महिलाओं के लिए लागू की गई थी। इस मामले को लेकर इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने कहा है कि कई मामलों में ऐसा हुआ हो सकता है कि योजना की लाभार्थी महिला के पास बैंक अकाउंट नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पतियों के अकाउंट का डिटेल्स दे दिया होगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल 28 जून को योजना की घोषणा हुई थी और आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर तय की गई थी। हो सकता है कि इस अवधि में कुछ पुरुषों द्वारा भी आवेदन किए गए, यह बात भी सामने आई है। यह भी जांच का विषय है कि क्या वास्तव में पुरुषों ने खुद आवेदन किया, या केवल उनके खाते का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच जारी है। जिन्होंने योजना का गलत फायदा उठाया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक मामले में एक व्यक्ति ने 30-35 अकाउंट योजना से जोड़े थे, ऐसे अकाउंट सील कर दिए गए हैं। इससे पहले भी अपात्र महिलाओं के आवेदन रद्द किए गए हैं।" इस योजना को लेकर एक और दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की साढ़े नौ हजार से ज्यादा महिला सरकारी कर्मचारियों ने भी इस योजना का लाभ उठाया है। कहा जा रहा है कि इन महिलाओं ने एक तरफ सरकार से सैलेरी भी ली और लाडकी बहिन योजना के 1500 रुपये भी लिए। लाडकी बहिन योजना मैने इस बारे में पिछले कई महीनों से यह जानकारी दी है कि जिन्होंने गलत तरीकों से योजना का लाभ लिया हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। जो पात्र हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो 14000 पुरुष हैं उसके बारे में डिटेल स्क्रूटनी की जाएगी, इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 26 लाख का डाटा दिया है। एक्चुअल जो अपात्र है वो ग्राउंड लेवल पर जांच करने के बाद ही पता चलेगा। प्रॉपर्ली हमें पात्र लाभार्थी को न्याय देना है। उनके पास जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं-कुछ फूड, परिवहन, ग्राम विकास आदि का भी डाटा इसमें हो सकता है।

गर्लफ्रेंड को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

पुणे – गर्लफ्रेंड ने शादी से जैसे ही इंकार किया, उसका प्रेमी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी से इंकार करने की वजह को लेकर एक प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। इस घटना गर्लफ्रेंड गंभीर रूप से घायल हो गई है। अब उसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, यह वारदात पुणे के करीबी चाकन इलाके के नानेकर वाडी में हुई है। जहां शादी से इंकार करने के बाद प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग के दूसरे मंजिल से सीधे नीचे फेंक कर उसे जान से मारने की कोशिश है। इस वारदात को अंजाम देने वाले प्रेमी का नाम सुरेश सिंह शिवकुमार है, जिसे चाकन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच कर रहीं पुलिस अधिकारी श्रेया कदम ने कहा कि अपराधी सुरेश सिंह का पिछले 9 साल से पीड़ित गर्लफ्रेंड से प्रेम संबंध चल रहे थे। पिछले 1 साल पहले पीड़ित गर्लफ्रेंड चाकन इलाके में स्थित एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। वह सुरेश सिंह से शादी भी करने वाली थी, लेकिन सुरेश सिंह अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करता था कि उसके किसी से नाजायज संबंध चल रहे हैं। सुरेश सिंह की इस हरकत से उसकी गर्लफ्रेंड भी परेशान हो चुकी थी। इसलिए उसने शादी नहीं करने का फैसला लिया था। जब सुरेश सिंह पीड़ित गर्लफ्रेंड के फ्लैट पर दाखिल हुआ और उसे शादी करने के बारे में पूछता रहा तब पीड़िता ने उसके साथ शादी करने से इनकार किया। इससे सुरेश सिंह आग बबूला हो गया और उसने पीड़िता को जान से मारने के उद्देश्य से बिल्डिंग के दूसरी मंजिल से सीधे नीचे फेंक दिया। इसके बाद सुरेश वहां से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पीड़िता को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पीड़ित प्रेमिका के सिर, पैर और पीठ में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी प्रेमी सुरेश सिंह शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध - डॉ. नीलम गोरहे

'संवेदनशीलता से संकल्प तक : शोषण के विरुद्ध संघर्ष' कार्यशाला

मुंबई – मानव तस्करी के विरुद्ध जनजागृति और जनआंदोलन का निर्माण आवश्यक है। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और मानव तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर सक्रिय कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है, ऐसा डॉ. नीलम गोरहे ने कहा। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर राज्य महिला आयोग द्वारा सह्याद्री अतिथिगृह में 'संवेदनशीलता से संकल्प तक: शोषण के विरुद्ध संघर्ष' शीर्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

गोरहे ने कहा कि महिलाओं का अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक और सशक्त होना बेहद ज़रूरी है। मानव तस्करी के ख़िलाफ़ काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाएँ और पुलिस, सरकार के साथ मिलकर काम करें तो इससे निपटने का रास्ता आसान होगा और इस अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। निर्देश हैं कि सरकार हर ज़िले की समीक्षा के बाद विकास संबंधी उद्देश्यों पर 3 प्रतिशत धनराशि खर्च करे। मानव तस्करी को बाल नीति और महिला नीति में शामिल किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि राज्य

सरकार महिला नीति और बाल नीति में नए निर्देश शामिल कर रही है। मानव तस्करी से जुड़े निर्देश और उपाय भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सरकार पीड़ितों के उचित पुनर्वास के लिए काम कर रही है। हालांकि, पीड़ितों को देखने का सामाजिक नजरिया बदलने की जरूरत है। महिलाओं और बच्चों में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करके इन समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न उपाय लागू किए जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस थानों में सूचना और परामर्श केंद्र भी हैं। टटकरे ने यह भी कहा कि अगर इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो बच्चों में जागरूकता पैदा करना आसान होगा। यद्यपि महिलाएँ हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं, फिर भी महिलाओं का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे ने स्पष्ट किया कि महिला सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमें समन्वय से काम करने की आवश्यकता है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कहा कि सैकड़ों वर्ष पूर्व क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले ने महिला स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। अब समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। पिछले तीन वर्षों में मानव तस्करी पर कार्य करते हुए आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस बल की मानव तस्करी निरोधक इकाई तथा ओमान के राजदूत के साथ मिलकर राज्य से 24 बालिकाओं और महिलाओं को मुक्त कराकर उनके परिजनों को सौंपा है। आयोग भविष्य में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तत्पर है। पहले सेमिनार में मानव तस्करी से निपटने के लिए तकनीक-आधारित मॉडल, उपकरण, नए विचारों और समाधानों पर चर्चा की गई। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य श्री ज्ञानेश्वर मुल्ये, स्टैंक टेक्नोलॉजीज के संस्थापक श्री अतुल राय, प्रेरणा संस्था की रश्मि टेलर और साइबरपीस फाउंडेशन के इरफान सिद्धवथम ने भाग लिया।

विशेषज्ञों ने मानव तस्करी रोकने के लिए उपलब्ध तरीकों और तकनीक-आधारित मॉडलों पर दुनिया भर से अपने अनुभव साझा किए। दूसरे सत्र यात्रा और ऑनलाइन मीडिया के दौरान मानव तस्करी के खिलाफ कार्य योजना में रेलवे स्टेशनों, राजमार्गों, बस स्टेशनों और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स जैसे ऑनलाइन स्थानों पर तस्करी की पहचान करने और उसे रोकने के तरीके पर चर्चा की गई। इसमें परिवहन, रेलवे, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एनजीओ, कानूनी विशेषज्ञों ने वर्तमान स्थिति, सुधार, समन्वय पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन प्रयास की शेरोन मेनेजेस ने किया।

इस अवसर पर पशुपालन, पर्यावरण परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मेघना बोर्डिकर, विधायक प्रज्ञा सातव, विधायक श्रीजया चव्हाण, विधायक मनीषा कायंदे, विधायक हारून खान, विधायक सना मलिक, राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव नंदिनी आवड़े, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, मानव तस्करी विरोधी पुलिस, विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी पुलिसकर्मी, मानव तस्करी के विरुद्ध कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। देश भर से आए विशेषज्ञ, संगोष्ठी में भाग लेने वाले वक्ता उपस्थित थे।

इंजीनियर ने कंपनी की 7वीं मंजिल से कूदकर दी जान

पुणे – एक कंपनी में काम करने वाली आईटी इंजीनियर ने अपनी ही कंपनी की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में मृतक ने अपने पिता से माफी मांगी है। हिंजेवाड़ी आईटी हब में एक 23 वर्षीय आईटी इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीयूष अशोक कवाडे ने ऑफिस मीटिंग के तुरंत बाद एटलस कंपनी की इमारत की सातवीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना सोमवार की सुबह 10 बजे हुई, जिससे पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार, पीयूष सीने में दर्द की शिकायत के बाद मीटिंग बीच में ही छोड़कर चले गए। वह आराम करने की बात कहकर बाहर निकले। कुछ ही मिनटों में पीयूष मृत पाए गए।

इस घटना के तुरंत बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पीयूष ने अपने पिता से इस आत्मघाती कदम के लिए माफी मांगी है। पीयूष ने कथित तौर पर यह भी कहा है कि वह जीवन के हर पहलू में असफल रहा है। पुलिस ने इस मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। वे यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या पीयूष काम के दबाव में था या फिर किसी निजी समस्या से जूझ रहा था।

एक दूसरे मामले में उत्तर प्रदेश के एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने लखनऊ में अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में सौम्या ने कहा कि उसके ससुराल वाले, जिसमें उसका देवर और पति भी शामिल हैं, उसे मारना चाहते हैं ताकि वह वह दोबारा शादी कर के। पुलिस ने वीडियो बरामद कर लिया है और मामले की व्यापक जांच की जा रही है। इसके लिए बीते दिनों ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति ने ऑफिस से देर से आने को लेकर पत्नी से झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक एक फैक्ट्री में मैनेजर था।

स्टोर से 6.52 लाख की जर्सी चोरी, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार

मुंबई – प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम के स्टोर से 6.52 लाख रुपये की जर्सी चोरी हो गई है। इस मामले में पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। स्टेडियम के सेकंड फ्लोर पर स्थित स्टोर से 6.52 लाख रुपये की जर्सी चुरा ली गई है। जर्सी चोरी करने का आरोप सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर लगा है। जानकारी के मुताबिक, लगभग 261 जर्सी चुराई गई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी सिक्योरिटी गार्ड फारुख असलम खान को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, वानखेड़े स्टेडियम की दूसरी मंजिल पर स्थित बीसीसीआई के आधिकारिक मर्चेंडाइज स्टोर से 6.52 लाख रुपये के मूल्य की 261 आधिकारिक आईपीएल खिलाड़ियों की जर्सी चोरी हुई है। जर्सी चोरी करने के आरोप में एक सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

साइबर ठगी : रश्मि शुक्ला और दया नायक का नाम लेकर लाखों ऐंठे

मुंबई – घाटकोपर इलाके में मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम लेकर महिला के साथ साइबर ठगी हुई है। इस घटना के सामने आने से हर कोई हैरान है। घाटकोपर इलाके में मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम लेकर महिला के साथ साइबर ठगी की घटना सामने आई है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ साइबर ठगों ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर बातचीत की और उससे 4 लाख रुपए की ठगी कर ली। फोन करने वाले ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस का डीसीपी दया नाईक और प्रमोद वर्मा बताया है। इसके अलावा साइबर ठगों ने यह भी दावा किया कि इस मामले में सीबीआई अधिकारी रश्मि शुक्ला खुद जांच करेंगी। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम का दुरुपयोग कर साइबर ठगी के इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। साइबर धोखाधड़ी के एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मुंबई के घाटकोपर की एक 40 वर्षीय महिला साइबर ठगों का शिकार हो गई। आरोपियों ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और आपराधिक जांच के बहाने उसपर 4 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला। इस दौरान आरोपियों ने मुंबई पुलिस के बड़े पुलिस अधिकारियों का नाम लिया और उनके गलत डेजिग्नेशन के साथ खुद को महिला के सामने पेश किया। अंधेरी में काम करने वाली शिकायतकर्ता को 19 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने दावा किया कि उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग कई बैंक खाते खोलने के लिए किया गया है, और वह कथित तौर पर एक वित्तीय अपराध में शामिल है। इसके बाद जालसाजों ने अपनी चाल को और आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो कॉल शुरू की, जिसमें पुलिस की वर्दी पहने दो लोगों ने खुद को क्राइम ब्रांच का डीसीपी दया नायक और प्रमोद वर्मा बताया। उन्होंने महिला को सख्त कार्रवाई की धमकी देकर धमकाया।

फौज में रहने वाले हकीमुद्दीन से मांगा नागरिकता का प्रमाण

पुणे – बीते दिनों भारतीय सेना से रिटायर्ड हो चुके बुजुर्ग से नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण मांगा गया। इस मामले में अब पुणे पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। एक रिटायर्ड फौजी से नागरिकता साबित करने के लिए जबरन दस्तावेज मांगने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुणे के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि घर के बाहर नारेबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के सीनियर अफसरों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ये भरोसा दिलाया गया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आरोप है कि 26 जुलाई की देर रात 30 से 40 लोगों ने रिटायर्ड सिपाही हकीमुद्दीन शेख के घर का घेराव कर दिया और उनसे दस्तावेज की मांग की।

दरअसल पुणे के रहने वाले हकीमुद्दीन शेख सेना से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मंगलवार की रात कुछ लोग उनके घर आए और नागरिकता का सबूत मांगने लगे। पुणे के चंदन नगर में रहने वाले हकीमुद्दीन ने कहा कि जिस वक्त लोगों ने उनके घर का घेराव किया उस वक्त लोकल पुलिस भी उनके साथ थी, लेकिन वो उपद्रवियों का साथ देती रही। साल 2000 में सेना से रिटायर होने के बाद 2013 में हकीमुद्दीन अपने मूल निवास प्रतापगढ़ लौट गए, लेकिन उनका परिवार पुणे में ही रहता है। पुणे पुलिस के डीसीपी सोमय मुंडे ने कहा कि पुलिस को इलाके में संदिग्ध अवैध प्रवासी होने की सूचना मिली थी। हमारी टीम ने वहां जाकर उनसे दस्तावेज मांगे, जिससे एक बार जब ये साफ हो गया कि वो भारतीय हैं तो हमने उन्हें जाने दिया।

भारत सरकार की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन हेतु अपील

नागपुर – जिले के सभी महाविद्यालयों एवं छात्रवृत्ति योजना के पात्र सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए, भारत सरकार की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति (फ्रीशिप), राजर्षि शाहू महाराज मेरिट छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु निर्वाह भत्ता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु महाडीबीटी पोर्टल 30 जून, 2025 से लागू कर दिया गया है। विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के आवेदन महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरें तथा पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति योजना के पात्र हैं, उनके छात्रवृत्ति योजना आवेदन महाविद्यालय द्वारा पंजीकृत कर समाज कल्याण कार्यालय में अनुमोदन हेतु जमा करें। समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

हाइवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली –'हाइवे पर अचानक ब्रेक लगाना एक्सीडेंट की स्थिति में लापरवाही माना जाएगा', सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजमार्ग पर अचानक और अघोषित ब्रेक लगाना लापरवाही माना जा सकता है, विशेषकर यदि किसी को इससे खतरा हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई कार चालक बिना किसी चेतावनी के हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाता है, तो उसे सड़क दुर्घटना की स्थिति में लापरवाही माना जा सकता है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने मंगलवार को कहा कि किसी चालक द्वारा राजमार्ग के बीच में अचानक वाहन रोकना, चाहे वह व्यक्तिगत आपातस्थिति के कारण ही क्यों न हुआ हो, उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए खतरा हो सकता है। पीठ के लिए फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि राजमार्ग पर वाहनों की तेज गति अपेक्षित है और यदि कोई चालक अपना वाहन रोकना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह सड़क पर पीछे चल रहे अन्य वाहनों को चेतावनी या संकेत दे।

यह फैसला इंजीनियरिंग के छात्र एस.मोहम्मद हकीम की याचिका पर आया, जिनका बायां पैर सात जनवरी, 2017 को कोयंबटूर में एक सड़क दुर्घटना के बाद काटना पड़ा था। यह घटना तब हुई जब हकीम की मोटरसाइकिल एक कार के पिछले हिस्से से टकरा गई जो अचानक रुक गई थी। परिणामस्वरूप, हकीम सड़क पर गिर गये और पीछे से आ रही एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। कार चालक ने दावा किया था कि उसने अचानक ब्रेक इसलिए लगाए क्योंकि उसकी गर्भवती पत्नी को उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि, अदालत ने इस स्पष्टीकरण को यह कहते हुए खारिज कर दिया, ''कार चालक द्वारा राजमार्ग के बीच में अचानक कार रोकने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण किसी भी

दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अदालत ने अपीलकर्ता को केवल 20 प्रतिशत की सीमा तक ही लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया, जबकि कार चालक और बस चालक को क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की सीमा तक लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया।

अदालत ने मुआवजे की कुल राशि 1.14 करोड़ रुपये आंकी, लेकिन अपीलकर्ता की सहभागी लापरवाही के कारण इसे 20 प्रतिशत कम कर दिया जिसका भुगतान दोनों वाहनों की बीमा कंपनियों द्वारा चार सप्ताह के भीतर उसे किया जाना है। इस मामले में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने कार चालक को दोषमुक्त करार दिया और अपीलकर्ता तथा बस चालक की लापरवाही को 20:80 के अनुपात में निर्धारित किया। इसने कार से पर्याप्त दूरी न बनाए रखने के लिए अपीलकर्ता को 20 प्रतिशत की लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने कार चालक और बस चालक को क्रमशः 40 और 30 प्रतिशत की सीमा तक और अपीलकर्ता को 30 प्रतिशत सहभागी लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया था।

CC MM YY KK

संपादक की कलम से

रोजगार के अवसर

सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, संयंत्रों के विस्तार तथा ऋण देने में सहायता मिलेगी जिससे सहकारिता से जुड़े करोड़ों सदस्य लाभान्वित होंगे, महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। शाह ने कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आगामी चार वर्षों के लिए कुल 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट किया। एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट्स में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने कहा कि "मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र पर चलते हुए 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने NCDC को आगामी चार वर्षों के लिए 500 करोड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है।

विकलांगता : बाधा नहीं, समाज का एक स्तंभ है

सोलापुर जिला प्रशासन और जिला परिषद के सहयोग से क्रियान्वित 'दिव्यांग व्यक्ति अस्मिता अभियान' केवल एक चिकित्सा प्रमाणपत्र अभियान नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों के आत्म-सम्मान, सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन का एक क्रांतिकारी प्रयास है। इस अभियान ने सोलापुर जिले के हजारों लाभार्थियों के लिए 21 प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त किया है। अतः यह निश्चित है कि विकलांगता, विकलांगता नहीं, बल्कि समाज का एक आधार स्तंभ बनेगी। दिव्यांगजनों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ' दिव्यांग व्यक्ति अस्मिता अभियान ' की रूपरेखा तैयार की गई।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, 21 प्रकार की विकलांगताओं के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य है और इसके लिए केंद्र सरकार की आत्मनिर्भरता योजना (यूडीआईडी कार्ड) का उपयोग किया जाता है। सोलापुर जिले के हजारों दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए जिला कलेक्टर कुमार आशीर्वाद की संकल्पना के तहत जिले में यह अभियान चलाया गया।

प्रारंभिक निरीक्षण और शिविर डिजाइन : निरीक्षण अवधि: 19 अगस्त से 26 सितंबर, 2024, कुल शिविर: 25, प्राथमिक जांच लाभार्थी: 18,421 विकलांग व्यक्ति, प्रमाण पत्र वितरण: पात्र 13,521 लाभार्थियों के घरों तक 90 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र वितरित किए गए, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच और अवलोकन,

दूसरा चरण: व्यापक शिक्षा के अंतर्गत 11

तालुकाओं के 1,010 बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों का आईक्यू परीक्षण। निरीक्षण स्थान: ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर 43 स्थानों पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण।

प्रशिक्षण और समन्वय कार्यशाला - जिले में इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। अभियान की शुरुआत में 16 कार्यशालाओं के माध्यम से 3,742 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया ।

हितधारक : स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, माता-पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, आदि।

होम डिलीवरी के लाभ और ब्रोशर - प्रमाण पत्र के साथ प्रदान की जाने वाली सामग्री: यूडीआईडी कार्ड, रेलवे रियायत प्रमाणपत्र, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी, शुभकामना पत्र प्रतिक्रिया के लिए पोस्टकार्ड (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)

प्रशासन की सक्रिय भागीदारी - अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी कुमार आर्शिवाद की संकल्पना से की गयी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम की देखरेख में अभियान को बहुत प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया। जबकि विशेषज्ञ पैनल: डॉ. रुत्विक जयकर, डॉ. सुहास माने, सुलोचना सोनावणे, मीनाक्षी वाकडे, डॉ. संपति टोडकर, डॉ. रोहन वैचल, कादर शेख।

मित्रा संस्था, मिशन संस्थान का योगदान अमूल्य रहा। इस प्रकार, जिला प्रशासन, जिला परिषद, स्वास्थ्य विभाग और मित्रा संस्था ने उचित समन्वय से जिले में दिव्यांग अस्मिता अभियान को सफल बनाया है।

'दिव्यांग वाटिका अस्मिता अभियान' सोलापुर जिले के दिव्यांग नागरिकों के लिए एक आदर्श बन गया है। चिकित्सा परीक्षण, सूचना संकलन, तकनीकी समन्वय, घर पहुँच सेवा और व्यापक प्रशिक्षण इन सभी तत्वों ने दिव्यांगों को न केवल सेवा प्रदान की है, बल्कि सम्मान भी प्रदान किया है। सूची के माध्यम से, 13521 दिव्यांगजनों को उनके घर पर ही विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। इसलिए, इन दिव्यांगजनों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए, इस अभियान के माध्यम से दिव्यांगजन एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं, और उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई देता है।

-सुनील सोनटक्के, जिला सूचना अधिकारी, सोलापुर

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 6 बड़े फैसले, किसान संपदा योजना के लिए 6520 करोड़ मंजूर

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी गई है। एनसीडीसी की कैपिटल 2000 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और रेलवे से जुड़े छह फैसले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दो फैसले किसानों से जुड़े हैं और चार फैसले रेलवे से जुड़े हैं। इस मीटिंग का आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुआ। बैठक में 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजन' के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी गई है। अब इस योजना का बजट बढ़कर कुल 6520 करोड़ पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की घटक योजना एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों को बनाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के तहत एनएबीएल मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इनकी स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये और 15वें वित्त आयोग के दौरान पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए 920 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

आईसीसीवीएआई और एफएसक्यूएआई दोनों ही योजनाएं पीएमकेएसवाई योजना का हिस्सा हैं। ये दोनों योजनाएं मांग के आधार पर चलती हैं। ऐसे में देश भर की पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिरुचि पत्र जारी किए जाएंगे। आओआई के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों के अनुसार उचित जांच के बाद अनुमोदित किया जाएगा। प्रस्तावित 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के कार्यान्वयन से इन इकाइयों के अंतर्गत विकिरणित खाद्य उत्पादों के प्रकार के आधार पर प्रति वर्ष 20 से 30 लाख मीट्रिक टन तक की कुल परिक्षण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित 100 एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना से खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए उन्नत अवसंरचना का विकास होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए एनसीडीसी को अधिक मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। इसकी कैपिटल 2000 करोड़ रुपए बढ़ाई गई है। सहकारिता की नई नीति हाल ही में लॉन्च की गई थी। एनसीडीसी जो कर्ज देती है, उसका नेट एनएपी शून्य है। इस योजना के तहत अगले चार साल तक हर साल 500 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। कुल 20 हजार करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। इससे करीब 13 हजार सहकारी सोसायटी और 3 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा।

इस बैठक में इटारसी से नागपुर के बीच चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। वहीं, अल्याबारी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। छत्रपति संभाजीनगर से प्रभानी लाइन को भी डबल करने की मंजूरी दी गई है। इससे रेल यातायात बेहतर होगा।

अजय देवगन संग धमाल मचाएंगी ईशा

बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता फिल्म 'धमाल 4' में अजय देवगन के साथ धमाल मचाती नजर आयेंगी। बॉलीवुड की ग्लेमरस और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार ईशा गुप्ता एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। इस बार वह कॉमेडी से भरपूर बहुचर्चित फिल्म धमाल 4 में नजर आयेंगी। इंद्र कुमार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में ईशा गुप्ता अजय देवगन के अपोज़िट एक अहम किरदार में नजर आएंगी। यह जोड़ी इस साल की सबसे दिलचस्प कास्टिंग मानी जा रही है। अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास से भरपूर स्क्रीन प्रेज़ेंस और दमदार अभिनय के लिए जानी जाने वाली ईशा अब धमाल यूनिवर्स में एक नई चमक लेकर आ रही हैं। धमाल 3 में उनके स्टाइल और तेवरों भरे किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब वह धमाल 4 में वापसी कर रही हैं। इस बार उनका किरदार और भी बोल्ड और कहानी में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला होगा। निर्देशक इंद्र कुमार ने कहा, हम बहुत खुश हैं कि ईशा गुप्ता दोबारा 'धमाल 4' में हमारे साथ हैं। वह 'धमाल 3' का भी हिस्सा रही थीं। वह एक बेहतरीन अभिनेत्री और शानदार इंसान हैं। उनके साथ काम करना हमेशा सुखद अनुभव होता है। हाल ही में ईशा ने हनी सिंह और जुबिन नौटियाल के साथ ब्राउन आइज़ वाली और इश्क मेरा जैसे म्यूज़िक वीडियोज़ में धमाल मचाया है। अब वह अपनी खास अदाओं और स्क्रीन पर दमदार उपस्थिति के साथ धमाल 4 में एक नई ताजगी लेकर आएंगी।

अनुपम खेर ने मां के जन्मदिन पर सुनाया किस्सा

अभिनेता अनुपम खेर के लिए आज का दिन बेहद खास है। उनकी मां दुलारी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनसे जुड़ा किस्सा सुनाया और बताया कि जब उन्होंने मां को जन्मदिन की बधाई दी, तो मां की प्रतिक्रिया मजेदार थी और उन्होंने कहा, तुझे याद कैसे है? इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, आज मां का हैप्पी बर्थडे है! जब मैंने उन्हें सुबह विश करने के लिए फोन किया, तो वह मुझसे पूछती है, 'तुझे कैसे याद है? मुझे मां का ये पूछना बड़ा अजीब लगा! पर फिर दुख भी हुआ कि मां-बाप बच्चों से उम्मीद ही नहीं करते कि बच्चों को बड़े हो जाने पर उनका जन्मदिन याद रहेगा! खेर ने आगे बताया, मेरी प्यारी माता! इस वीडियो में मैंने छोटी सी कोशिश की है कि मुझे आपके बारे में क्या-क्या याद है, सब बताऊं। आपने मुझे जन्म दिया! मुझे सब कुछ याद है और आखिरी सांस तक याद रहेगा!

पंकज त्रिपाठी ने शुरू की नई फिल्म की शूटिंग

'क्रिमिनल जस्टिस 4' की सफलता का आनंद ले रहे अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपनी अगली अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री अदिति राव हैदरी नजर आएंगी। गुरुवार को पंकज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को जानकारी दी। शेयर किए गए पोस्ट के जरिए पंकज त्रिपाठी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग लखनऊ में शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का टाइटल 'परिवारिक मनुरंजन' है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेट से अपनी और अभिनेत्री अदिति राव हैदरी की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें एक तस्वीर में वह अदिति को देखकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। यह फिल्म पंकज और अदिति की पहली ऑनस्क्रीन जोड़ी होगी। पंकज ने कैप्शन में लिखा,परिवार, हंगामा और पारिवारिक माहौल! 'परिवारिक मनुरंजन' की शूटिंग वरुण वी. शर्मा के निर्देशन में शुरू।

दो साल तक डिप्रेशन में रहीं पायल घोष

अभिनेत्री पायल घोष ने बताया कि पिछले दो सालों से वह काम न मिलने के कारण डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रही थीं। उन्होंने बताया कि इस मुश्किल दौर में उन्हें न तो इंडस्ट्री से और न ही परिवार या दोस्तों से कोई सहारा मिला। वह पूरी तरह अकेली थीं और कई बार घर में बंद रहकर रोती थीं। पायल ने अपनी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टरों की मदद और दवाइयों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि दो साल तक काम न मिलना बहुत मुश्किल था, जिससे उनकी बचत भी खत्म होने लगी थी।

पायल ने बताया, न तो मुझे इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट मिला, चाहे वो मेरे जानने वाले हों या जिनके साथ मैंने पहले काम किया हो और न ही मेरे प्रियजनों से। यह सब मेरे लिए अकेलापन भरा था। हर एक्टर ऐसे दौर से गुजरता है, जब आप चाहे जो भी कोशिश करें, सब कुछ आपके खिलाफ काम कर रहा होता है और कुछ भी आपके पक्ष में काम नहीं कर रहा होता। पिछले दो साल मेरे लिए ऐसे ही रहे। ऐसे कई मौके आए, जब मैं अकेले रोई हूं। चिंता, तनाव और सदमे से खुद को घर में बंद करके कई दिन बिताए हैं। चाहे मेरा परिवार हो या इंडस्ट्री, मुझे किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला और मैं घर पर अकेली थी। पायल ने बताया कि उन्हें बढ़ती परेशानियों के लिए पेशेवरों की मदद लेनी पड़ी, अकेलेपन ने मुझे बहुत परेशान किया और इसने मेरे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। मुझे उन पूरे 2 सालों के लिए पेशेवर मदद और दवा का सहारा लेना पड़ा और हर दिन एक बुरे सपने की तरह था। 2 साल तक बिना काम के रहना एक लंबा समय है। मेरी बचत खत्म हो रही थी, जिंदगी पर असर पड़ रहा था। हालांकि, अब धीरे-धीरे उनके लिए काम के मौके बढ़ रहे हैं और चीजें बेहतर हो रही हैं। पायल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनके प्रोजेक्ट्स दर्शकों तक पहुंचेंगे और चीजें बेहतर होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह नहीं चाहतीं कि कोई और इस तरह के तनाव और एंग्जाइटी से गुजरे। उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे स्थिति ठीक हो रही है, भगवान की कृपा से अब धीरे-धीरे और लगातार चीजें बेहतर हो रही हैं और काम के ऑफर मिलने लगे हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि जल्द मेरा काम दर्शकों के लिए सामने आएगा।

यह पत्र मालक, मुद्रक, प्रकाशक मिलिंद दहीवले ने एम.पी.ऑफसेट सिरसपेठ चौक, उमरेड़ रोड, नागपुर यहां से मुद्रित कर कार्यालय - फ्लैट नंबर 204, दूसरा माला, साकेत अपार्टमेंट, फूलमती ले-आउट, आरोग्यम क्लीनिक के पास, नागपुर-440027 से प्रकाशित किया. मिलिंद दहीवले, मो.9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईट: www.kendriyamanvadhikar.com

This paper is printed by owner, printer and publisher Milind Dahiwale at MP Offset, Siraspeth Chowk, Umred Road, Nagpur and published from office Flat No. 204, Second Floor, Saket Apartment, Phulmati Layout, Near Arogya Clinic, Nagpur 440027. Milind Dahiwale Mobile No. 9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईट: www.kendriyamanvadhikar.com

केन्द्रीय मानवाधिकार समाचार पत्र में प्रकाशित सभी लेख, छायाचित्र पर संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। न्यायिक कार्यवाही केवल नागपुर न्यायालय में होगी।

महाराष्ट्र सरकार 1,000 करोड़ रुपये मूल्य के 1-2 वर्षीय बॉन्ड बेचेगी

मुंबई - महाराष्ट्र सरकार के 1000 करोड़ रुपये के 12 वर्षीय '6.76% महाराष्ट्र सरकारी बॉन्ड, 2037' (23 अप्रैल 2025 को जारी) की बिक्री सरकार की संशोधित अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार के विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, वित्त विभाग की सचिव शैला ए. ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया।

गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी पद्धति (संशोधित) के अनुसार, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत पात्र व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। हालाँकि, किसी निवेशक को कुल अधिसूचित राशि का अधिकतम 1 प्रतिशत ही आवंटित किया जाएगा। यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 जुलाई, 2025 को मुंबई स्थित अपने कार्यालय में आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए बोलियां 29 जुलाई, 2025 को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक, कोर बैंकिंग समाधान, (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जानी हैं।

प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामी के परिणाम उसी दिन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएँगे। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि का भुगतान 30 जुलाई, 2025 को बैंक के कार्य समय समाप्त होने से पहले नकद, बैंकर्स चेक/पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में उनके खाते पर आहरित चेक के माध्यम से किया जाएगा। बॉन्ड की अवधि 12 वर्ष है और यह 23 अप्रैल, 2025 से शुरू होगा और 23 अप्रैल, 2037 को पूरी तरह से चुकाया जाएगा। ब्याज दर 6.76 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। बॉन्ड की मूल कीमत पर मूल तिथि से प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर और 23 अप्रैल को अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए पात्र माना जाएगा। ये प्रतिभूतियाँ पुनर्विक्रय और खरीद के लिए स्वीकार्य होंगी, वित्त विभाग ने सूचित किया है।

महाराष्ट्र सरकार के 13 वर्षीय 1000 करोड़ रुपये के '6.72% महाराष्ट्र सरकारी बॉन्ड, 2038' (23 अप्रैल 2025 को जारी) की बिक्री सरकार की संशोधित अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार के विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, यह जानकारी वित्त विभाग की सचिव शैला ए. ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दी।

गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी पद्धति (संशोधित) के अनुसार, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत पात्र व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। हालाँकि, किसी निवेशक को कुल अधिसूचित राशि का अधिकतम 1 प्रतिशत ही आवंटित किया जाएगा।

यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 जुलाई, 2025 को मुंबई स्थित अपने कार्यालय में आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए बोलियां 29 जुलाई, 2025 को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक, कोर बैंकिंग समाधान, (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जानी हैं।

प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामी के परिणाम उसी दिन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएँगे। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि का भुगतान 30 जुलाई, 2025 को बैंक के कार्य समय समाप्त होने से पहले नकद, बैंकर्स चेक/पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में उनके खाते पर आहरित चेक के माध्यम से किया जाएगा।

बॉन्ड की अवधि 13 वर्ष है और यह 23 अप्रैल, 2025 से शुरू होगा और 23 अप्रैल, 2038 को पूरी तरह से चुकाया जाएगा। ब्याज दर 6.76 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। बॉन्ड की मूल कीमत पर मूल तिथि से प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर और 23 अप्रैल को अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश को वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए पात्र माना जाएगा। ये प्रतिभूतियाँ पुनर्विक्रय और खरीद के लिए स्वीकार्य होंगी, वित्त विभाग ने सूचित किया है। महाराष्ट्र सरकार के 1000 करोड़ रुपये के 14 वर्षीय '6.75% महाराष्ट्र सरकारी बॉन्ड, 2039' (23 अप्रैल 2025 को जारी) की बिक्री सरकार की संशोधित अधिसूचना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार के विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, वित्त विभाग की सचिव शैला ए. ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया। गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी पद्धति (संशोधित) के अनुसार, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत पात्र व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। हालाँकि, किसी निवेशक को कुल अधिसूचित राशि का अधिकतम 1 प्रतिशत ही आवंटित किया जाएगा।

यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 जुलाई, 2025 को मुंबई स्थित अपने कार्यालय में आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए बोलियां 29 जुलाई, 2025 को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक, कोर बैंकिंग समाधान, (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जानी हैं। प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के अनुसार कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामी के परिणाम उसी दिन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएँगे। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि का भुगतान 30 जुलाई, 2025 को बैंक के कार्य समय समाप्त होने से पहले नकद, बैंकर्स चेक/पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में उनके खाते पर आहरित चेक के माध्यम से किया जाएगा।

महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण की चुकौती, 2025 जुटा लिया

मुंबई - महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही खुले बाजार से 8.29% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण 2025 जुटा लिया है। ऋण की बकाया राशि 26 अगस्त, 2025 को 25 अगस्त, 2025 तक देय ब्याज सहित सममूल्य पर चुकाई जाएगी, वित्त विभाग (वित्तीय सुधार) की सचिव श्रीमती शैला ए. ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया। यदि महाराष्ट्र सरकार 'परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881' के अंतर्गत उपरोक्त तिथि को अवकाश घोषित करती है, तो राज्य अग्रिम कार्यालय पिछले कार्यदिवस को ऋण चुका देगा। 26 अगस्त, 2025 के बाद इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24 (2) और 24 (3) के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों के पंजीकृत धारक से द्वितीयक सामान्य खाता बही या प्रतिभूति प्रमाणपत्रों के रूप में परिपक्वता आय का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जमा सुविधा वाले किसी भी बैंक में धारक के खाते में जमा करके और भुगतान आदेश के माध्यम से उसके बैंक खाते के प्रासंगिक विवरण के साथ किया जाएगा। प्रतिभूतियों के भुगतान के मामले में, मूल अभिदाता या ऐसी प्रतिभूतियों का उत्तराधिकारी धारक, जैसा भी मामला हो, अपने बैंक खाते का प्रासंगिक विवरण बैंक या कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा के उप-कोषाध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, अपने सहायक बैंकों को, यदि वे ब्याज भुगतान के लिए नामित/पंजीकृत हैं, प्रस्तुत करेगा। हालाँकि, संबंधित बैंक खाता विवरण/इलेक्ट्रॉनिक जमा आदेश के अभाव में, नियत तिथि पर पुनर्भुगतान की सुविधा के लिए, 8.29% महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 2025 के धारकों को अपने बांड लोक ऋण कार्यालय में 20 दिन पहले प्रस्तुत करने चाहिए। बांड के पीछे एक उपयुक्त नोट के साथ पुनर्भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि प्रमाणपत्र पर देय मूल राशि प्राप्त हो गई है। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि प्रतिभूतियाँ प्रतिभूति प्रमाण-पत्र के रूप में हैं, तो उन स्थानों पर जहाँ भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी सहयोगी बैंक के माध्यम से कोषागार का कार्य किया जाता है, उन्हें संबंधित बैंक की शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि कोषागार या उप-कोषागार में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बॉन्ड को पंजीकृत और बीमित डाक द्वारा संबंधित लोक ऋण कार्यालय को विधिवत पते पर भेजना होगा। वित्त विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लोक ऋण कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य में सरकारी खजाने के रूप में कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंक की किसी भी शाखा के कोषागार/उप-कोषागार पर आहरित नकद ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करेगा।

दिल्ली में शाह, सीतारमण, चौहान से मिले मुख्यमंत्री फडणवीस

नई दिल्ली - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीमेंट सड़कों से जुड़ेंगे गांव, सीवेज ट्रीटमेंट, बांस क्लस्टर, विदर्भ में उर्वरक परियोजना, एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए एआई, कई परियोजनाओं में तेजी आएगी। राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा के लिए पिछले दो दिनों में दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की। ये बैठकें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और नीति आयोग के साथ हुईं। मुख्यमंत्री ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने महाराष्ट्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और मुद्दों पर चर्चा की। यह मुलाकात लगभग 25 मिनट तक चली। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शिष्टाचार भेंट की और उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्रीय आर्थिक मामलों के मंत्रालय से अनुमति मांगी। निर्मला सीतारमण ने सभी मानकों पर अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र की प्रशंसा की। इन परियोजनाओं में 1000 की आबादी वाले गांवों को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ने की परियोजना शामिल है।

सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री ने की लोक निर्माण विभाग की 150 दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा

मुंबई - सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से विकसित महाराष्ट्र के 150 दिवसीय कार्ययोजना, ई-गवर्नेंस सुधार और सेवा-संबंधी प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग द्वारा किए जा रहे विविध कार्यों और उपक्रमों की समीक्षा की। लोक निर्माण मंत्री शिवेन्द्रसिंहराजे भोसले की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित बैठक में लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सचिव संजय दशपुते और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लोक निर्माण मंत्री शिवेन्द्रसिंहराजे भोसले ने कहा कि राज्य में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए 150 दिवसीय कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग निर्धारित समय-सीमा में कार्य कर विकास कार्यों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों में भी विभाग की विशिष्टता सिद्ध करे।

लोक निर्माण विभाग के 150 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा करते हुए मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने कहा कि विभाग की वेबसाइट को अद्यतन किया जाए और अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवा संबंधी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। इसमें सेवा प्रवेश नियम, संरचना, अनुकंपा नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति प्रक्रिया संबंधी कार्य शीघ्रता से किए जाएं।

'विकसित महाराष्ट्र 2047' में लोक निर्माण विभाग के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से काम करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने विज़न डॉक्यूमेंट का मसौदा समय सीमा के भीतर पूरा करने का सुझाव भी दिया। लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने एक बैठक में मंत्रालय क्षेत्र में बन रहे नए भवन निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सचिव संजय दशपुते और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लोक निर्माण मंत्री शिवेन्द्रसिंहराजे भोसले ने संबंधितों को नए मंत्रालय भवन का निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू

मुंबई - भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह चुनाव 'राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952' और उसके अंतर्गत बनाए गए 'राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974' के अंतर्गत आयोजित किया जाता है।

आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस प्रारंभिक प्रक्रिया के पूरा होने के तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। भारत के चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस चुनाव से पहले उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल की तैयारी, मुख्य रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति, तथा पिछले सभी उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए संदर्भ सामग्री की तैयारी और प्रसार शामिल हैं।

महाराष्ट्र राज्य कर विभाग ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में 20.20 करोड़ की कर चोरी का खुलासा किया

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य माल और सेवा कर विभाग द्वारा एक व्यावसायिक इकाई मेसर्स सूर्या एंटरप्राइजेज के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में, इकाई के मालिक, निखिल नरेश वालेचा (28 वर्षीय) को कुल 20.20 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

यह व्यावसायिक इकाई 8 सितंबर, 2021 को माल और सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत थी, और यह देखा गया है कि संबंधित व्यक्ति ने वास्तव में कोई सामान या सेवा प्राप्त किए बिना और किसी भी सामान का आदान-प्रदान किए बिना फर्जी चालान के आधार पर धोखाधड़ी से आईटीसी प्राप्त किया है। जाँच के दौरान, व्यवसाय के पंजीकृत पते पर जाकर, यह पाया गया कि अभियुक्तों ने गैर-मौजूद संस्थाओं के माध्यम से 17.03 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी प्राप्त किया था और 3.03 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आईटीसी

जीएसटी रिटर्न में गलत तरीके से दिखाया गया था। इन लेन-देन के बदले वास्तव में कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं हुई थी।

उल्हासनगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निखिल वाले को 30 जुलाई 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा फर्जी बिलों और फर्जी लेन-देन के माध्यम से कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए शुरू किए गए विशेष जांच अभियान के तहत की गई। राज्य कर सहायक आयुक्त संतोष लोंढे, कर अधिकारी दीप्ति पिलारे, सुजीत कक्कड़, संतोष खेडकर के साथ-साथ निरीक्षकों और कर सहायकों की एक विशेष टीम की मदद से यह कार्रवाई की गई। संपूर्ण जांच राज्य कर संयुक्त आयुक्त (जांच-सी), मुंबई के आदेश और राज्य कर उपायुक्त यास्मीन अजीम मोलकर के मार्गदर्शन में की गई।

यह कार्रवाई चालू वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य जीएसटी विभाग द्वारा की गई पांचवीं गिरफ्तारी है और विभाग ने कहा है कि कर चोरी, फर्जी चालान बनाने, गलत कारोबार दिखाने और अवैध रूप से आईटीसी प्राप्त करने या स्थानांतरित करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

झूठी शान के लिए मां ने करवाया बेटी का कत्ल, पुलिस ने हिरासत में लिया

कराची - पाकिस्तान से एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया था। यहां बलूचिस्तान प्रांत में एक युवक और युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में युवती की मां को अदालत ने पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने बलूचिस्तान प्रांत में झूठी शान के नाम पर अपनी बेटी और एक युवक की कथित हत्या के मामले में एक महिला को बृहस्पतिवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। यह घटना कुछ दिन पहले क्वेटा के पास संजीदा डेगरी इलाके में हुई थी। गुल जान बीबी नाम की महिला को तक गिरफ्तार किया गया था जब हत्या का वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में महिला ने बलूच जनजातीय रीति-रिवाजों का हवाला देते हुए इन हत्याओं को उचित ठहराया था।

आरोपी महिला को क्वेटा स्थित आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) के समक्ष

पेश किया गया था। अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वीडियो में, गुल कुरान पकड़े हुए दिखाई दे रही है और कह रही है कि यह कृत्य कोई अपराध नहीं था, बल्कि पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप था। उसने वीडियो संदेश में कहा, ''मेरी बेटी शादीशुदा थी और पांच बच्चों की मां थी। उसकी हत्या एक बलूच युवक के साथ उसके संबंधों के कारण की गई। यह युवक हमारे परिवार द्वारा कई चेतावनियों के बावजूद टिक टॉक पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करता रहता था।''

आरोपी महिला ने कहा, ''बलूची संस्कृति में, अवैध संबंध रखना एक अपराध है और इसके लिए मौत की सजा है। गोली मारने का फैसला एक जिरगा (कबीलाई परिषद) ने लिया था।'' पुलिस ने इस मामले के संबंध में एक कबायली नेता और 10 अन्य को भी गिरफ्तार किया है। यह मामला पिछले सप्ताह तब सुर्खियों में आया था जब वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में नजर आता है कि गुल की बेटी और उसके पुरुष मित्र को एक पहाड़ी इलाके में कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी।

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि झूठी शान की खातिर हत्या करने के इस मामले में 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा था कि मामले की जांच जारी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने संदिग्धों को "जानवर" करार देते हुए कहा था कि वो किसी भी रियायत के हकदार नहीं हैं।

फिलीपींस में ऊष्ण कटिबंधीय तूफान से मची तबाही, करीब 25 लोगों की हुई मौत

मनीला - ऊष्ण कटिबंधीय तूफान ने फिलीपींस में भीषण तूफान के साथ बारिश और बाढ़ ने फिलीपींस में 25 लोगों की जान ले ली है। काफी संख्या में बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित गांवों में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर ले जाया गया है। फिलीपींस में ऊष्ण कटिबंधीय तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। भीषण तूफान के साथ बारिश और बाढ़ ने फिलीपींस में 25 लोगों की जान ले ली है। काफी संख्या में बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित गांवों में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर ले जाया गया है। इसके उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में ऊष्ण कटिबंधीय तूफान से मौसम की स्थिति और बिगड़ गयी है। 165 किलोमीट प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। तूफान 'को-मे' ने बृहस्पतिवार रात को पंगासिनान प्रांत के अग्नो कस्बे में दस्तक दी और इस दौरान 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं ने भीषण तबाही मचाना

शुरू कर दिया। हालांकि अब उत्तरपूर्व की ओर बढ़ रहा यह तूफान धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है और शुक्रवार सुबह इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई।

फिलीपींस में तूफान के कारण हुई तेज बारिश और बाढ़ ने लैंड्स्लाइड बढ़ा दी। इससे भयानक नुकसान हुआ। आपदा प्रतिक्रिया अधिकारियों को गत सप्ताहांत से अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत की खबरें मिली हैं जिनमें से ज्यादातर लोगों की मौत अचानक बाढ़ आने, पेड़ उखड़ने, भूस्खलन और करंट लगने के कारण हुई है। आठ अन्य लोग लापता हैं। 'को-मे' से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

सरकार ने तूफान से मची तबाही को देखते हुए शुक्रवार को तीसरे दिन महानगर मनीला में स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है और उत्तरी लुजोन क्षेत्र में 35 प्रांतों में कक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित गांवों में लोगों को बचाने के लिए हजारों सैन्य कर्मियों, पुलिस, तटरक्षक कर्मियों, दमकल कर्मियों और स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है।

बीयर बार में सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाला उपविभागीय अभियंता को निलंबित कर दिया गया है

नागपुर – नागपुर के बीयर बार में सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले की पहचान हो गई है। ऐसा करने वाले उपविभागी अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। नागपुर के बीयर बार में सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने वालों की पहचान हो गई है। फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाला पीडब्ल्यूडी का उपविभागी अभियंता निकला। जानकारी के मुताबिक, इनके बीच गढ़चिरौली जिले के चामोर्शी में हुए एक्सेस वर्क की डीलिंग हुई थी। इस मामले में एक्शन लेते हुए उपविभागी अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। अब ठेकेदार और उसके साथी पर मामला भी दर्ज होगा।

पिछले तीन दिनों से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें नागपुर के एक बार में शराब की चुस्की के साथ सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर किए जाने के वीडियो था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सरकारी कार्यालय में हड़कंप मचा था। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार हरकत में आई एवं महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जांच के आदेश दिए थे।

नागपुर में बीयर बार में जिन सरकारी फाइलों पर सरकारी हस्ताक्षर हुए थे, वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की फाइलें निकली। यह फाइल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के चामोर्शी मे हुए अतिरिक्त कार्य से जुड़ी हुई थी। वीडियो में जो अधिकारी फाइल पर हस्ताक्षर कर रहा है, उसकी पहचान चामोर्शी के डिप्टी इंजीनियर के रूप में हुई है। डिप्टी इंजीनियर के साथ बार में जाने वाले ठेकेदार और उनके साथी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को दिया है। वीडियो में जो अधिकारी फाइल पर हस्ताक्षर कर रहा है, उसकी पहचान चामोर्शी के उपविभागीय अभियंता देवानंद सोनटके के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित उप विभागीय अभियंता नागपुर के बीयर बार में बैठा था। इस दौरान उसने एक सरकारी फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए। इस करतूत को मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद गढ़चिरौली का लोकनिर्माण विभाग हरकत में आया और चामोर्शी के उपविभागीय अभियंता सोनटके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

न्यूज गैलरी

छात्रा को हाफ न्यूड होकर वीडियो कॉल करती थी 35 साल की टीचर, गिरफ्तार

मुंबई – 10वीं क्लास के लड़के के साथ हाफ न्यूड होकर वीडियो कॉल करती थी 35 साल की टीचर, खुली पोल तो हुई गिरफ्तार। नवी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला टीचर, 10वीं क्लास के लड़के के साथ हाफ न्यूड होकर वीडियो कॉल करती थी। लड़के की मां की शिकायत पर टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। 35 साल की महिला टीचर, 10वीं क्लास के एक लड़के के साथ हाफ न्यूड होकर अश्लील वीडियो चैटिंग करती थी। जब लड़के की मां को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद आरोपी महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक नाबालिग लड़के के साथ अश्लील चैटिंग करने वाली शिक्षिका को कोपरखैरने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया था, कोर्ट ने उसे 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर महिला, उस नाबालिग बच्चे के अलावा और कितने लोगों से इस तरह की हरकत करती थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग लड़के की मां ने मोबाइल में महिला का अर्धनग्न वीडियो देख लिया। कोपरखैरने पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाले एक नाबालिक लड़के की पहचान इंस्टाग्राम पर उल्वे क्षेत्र में रहनेवाली 35 वर्षीय महिला से हुई थी। समय के साथ उनकी जान-पहचान दोस्ती में बदल गई।

मालिक की कार का शीशा तोड़कर 25 लाख रुपये चोरी

नागपुर – पेट्रोल पंप मालिक की कार से बदमाशों ने दिनदहाड़े 25 लाख रुपये लूट लिए। बदमाशों ने कार का शीशा तोड़ा और पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए। नागपुर जिले में लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के तहत फराज सिद्दकी नामक एक पेट्रोल पंप मालिक की कार का शीशा तोड़कर अज्ञात चोरों ने 25 लाख रुपये से भरा हुई बैग चोरी कर लिया। यह घटना श्रीराम टॉवर परिसर के सामने हुई, जहां वह अपने एक कारोबारी मित्र से मिलने के लिए कुछ देर तक रुके हुए थे। जानकारी के अनुसार, फराज सिद्दकी अपने व्यवसायिक पार्टनर के ऑफिस से 25 लाख रुपये कैश लेकर निकले थे। इस दौरान उन्हें श्रीराम टॉवर में अपने एक मित्र से मिलना था। टॉवर की पार्किंग में जगह न मिलने के कारण उन्होंने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी और मित्र से मिलने चले गए। इसके कुछ समय बाद जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी कार का बीच वाला शीशा टूटा हुआ था और अंदर रखा कैश से भरा बैग गायब था। यह देख वे हैरान रह गए और तुरंत सदर पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई। सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया यह मामला सुनियोजित प्रतीत हो रहा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या चोर पहले से ही फराज सिद्दकी का पीछा कर रहे थे। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि चोरों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

माधुरी मिसाल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 20 लाख का चेक भेंट किया

मुंबई – राज्य के नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाल ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक उल्लेखनीय पहल लागू की और मुख्यमंत्री सहायता कोष में 20 लाख रुपये का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपील की थी कि वे जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए तख्तियों, बैनरों और गुलदस्तों पर पैसा खर्च करने के बजाय मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें। इसी अपील के अनुरूप यह पहल शुरू की गई है।

छात्रों अर्धवार्षिक उपस्थिति और बैंक विवरण अपडेट करें

नागपुर – भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना वर्ष 2016-17 से छात्रों के लिए लागू की गई थी। पिछड़े वर्ग के सरकारी छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध वर्ग के छात्र-छात्राओं जैसे छात्रों को भोजन, आवास, शिक्षण सामग्री, निर्वाह भत्ता और अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए यह राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना में संशोधन किया गया है और वर्ष 2024-25 में, स्वाधार योजना के लिए https://hmas.mahait.org पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों के लिए अर्धवार्षिक उपस्थिति और बैंक विवरण भरने हेतु एक टैब उपलब्ध

कराया गया है। समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे ने छात्रों से अपनी अर्धवार्षिक उपस्थिति और बैंक विवरण अपडेट करने की सार्वजनिक अपील की है। अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, शासकीय आई.टी.आई. समारोह, श्रद्धानंद पेठ, दीक्षाभूमि चौक, नागपुर में संपर्क करें।

नापतौल विभाग का मंगलवार को जनता दरबार

नागपुर – नापतौल प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने, जनसंपर्क को मजबूत करने और उपभोक्ता शिकायतों के समय पर समाधान के उद्देश्य से, जिला क्रमांक 1 और 2 के नापतौल उप नियंत्रक अगस्त 2025 से प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जनता दरबार का आयोजन कर रहे हैं। नापतौल विभाग के उप नियंत्रक, वी. भा. झोटे ने सभी हितधारकों से उपस्थित होने की अपील की है। नागपुर और वर्धा जिलों के सामान्य उपभोक्ता, उपभोक्ता संगठन, पैकेज्ड सामान के निर्माता, पैकर, आयातक, खुदरा विक्रेता और व्यापारी, साथ ही बाट-माप के लाइसेंसधारी निर्माता, सुधारक और विक्रेता, नापतौल उप नियंत्रक कार्यालय, प्रशासनिक भवन क्रमांक 2ए विंग, पाँचवीं मंजिल, सिविल लाइंस, नागपुर से संपर्क करें।

सितंबर 2025 तक 5000 मेगावाट की सौर कृषि परियोजनाएं पूरी करें

मुंबई – मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 मेरी महत्वाकांक्षी योजना है। सितंबर 2025 तक 5000 मेगावाट का लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना के काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को इस योजना का काम तेजी से और

समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस सह्याद्रि अतिथिगृह में मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के लिए भूमि उपलब्धता और अन्य संबंधित मुद्दों पर आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, गैर-परंपरागत ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना बोर्डिकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 मेरी सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। निजी और सरकारी स्थानों पर विकसित की जा रही सौर परियोजनाओं के लिए स्थानीय एजेंसियों को समन्वय से काम करना चाहिए। जिला-स्तरीय टास्क फोर्स को समय-समय पर इस योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। किए जाने वाले कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने चाहिए और डेवलपर्स के सामने आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने यह भी निर्देश दिया कि जिलेवार काम में इस तरह तेजी लाई जाए कि सितंबर 2025 तक मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 योजना के माध्यम से पांच हजार मेगावाट तक बिजली उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर वैकल्पिक भूमि के पट्टे देने, फसल अतिक्रमण हटाने, स्थायी संरचनाओं के अतिक्रमण हटाने, सड़कों के पुनर्निर्माण और आवश्यकतानुसार समय पर भूमि की माप और सीमांकन करने और ग्राम पंचायतों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के काम को प्राथमिकता दें। यदि सौर परियोजना की कोई सामग्री चोरी हो जाती है, तो पुलिस को तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में योजना पर काम करते समय उचित देखभाल की जानी चाहिए। पेड़ों के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, यदि बिजली की लाइन वन क्षेत्र से गुजरती है, तो वन विभाग द्वारा जल्द से जल्द अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि वन विभाग निर्धारित समय के भीतर निजी और निकटवर्ती वन क्षेत्रों के लिए अनापत्ति परमिट जारी करने की कार्रवाई करे।

इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, ग्राम विकास विभाग के एकनाथ दावले, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महापारेषण के प्रबंध निदेशक डॉ. संजीव कुमार, महानिमति के प्रबंध निदेशक डॉ. राधाकृष्णन बी. महाऊर्जा विकास संस्था के महानिदेशक ओमप्रकाश बकोरिया, सभी जिला कलेक्टर, सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

गढ़चिरौली जिले में जल संरक्षण की ऐतिहासिक सफलता

मुंबई – गढ़चिरौली जिले ने गाद मुक्त बांध गाद मुक्त शिवार अभियान के तहत जल संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। गढ़चिरौली ने कम समय में रिकॉर्ड जलाशय बनाकर पूरे राज्य के लिए एक मिसाल कायम की है। इस वर्ष मानसून 20 दिन पहले शुरू हो गया, जिससे कार्य की अवधि कम हो गई, लेकिन जिला प्रशासन के प्रभावी समन्वय और निरंतर प्रयासों से यह बड़ी सफलता हासिल हुई, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के क्षेत्र में गढ़चिरौली जिले को मिली सफलता पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रेरणादायक है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है।

गढ़चिरौली जिले के 97 गांवों में जलाशयों का निर्माण किया गया है और अकेले वर्ष 2025-26 में 64.5 करोड़ लीटर जल भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है। इससे हजारों नागरिकों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। खास बात यह है कि इस वर्ष 6,44,601 घन मीटर गाद निकाली गई, जो पिछले दो वर्षों के संयुक्त प्रदर्शन से आठ गुना अधिक है। इन कार्यों में विभिन्न सामाजिक संगठनों और संघों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि में जिला प्रशासन, यानी गढ़चिरौली जिला कलेक्टर की प्रमुख भूमिका है। इससे यह देखा जा सकता है कि यदि जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय और जनता मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। गढ़चिरौली ने दिखा दिया है कि योजनाबद्ध तरीके से और तकनीकी मार्गदर्शन से जल सुरक्षा के लिए एक बड़ी छलांग लगाई जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सफल मॉडल का अध्ययन करने के बाद, इस तरह की पहल पूरे राज्य में लागू की जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल संरक्षण से कृषि, जन-जीवन और पर्यावरण को स्थिरता मिलेगी।

विधान भवन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि दी गई

मुंबई – लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्य तिथि के अवसर पर महाराष्ट्र विधान सभा सचिवालय के सचिव (1), जीतेन्द्र भोले, सचिव (2), श्रीमती मेघना तालेकर, सचिव (3), डॉ. विलास अठावले और सचिव (4), शिवदर्शन सत्ये ने विधान भवन में उनकी आधी लंबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सचिव सुनील वाणी, महाराष्ट्र विधान सचिवालय के उप सचिव विजय कोमटवार और अवर सचिव (समितियां) सुरेश मोगल सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी लोकमान्य तिलक की आधी लंबाई वाली प्रतिमा पर गुलाब के फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे ने राजस्व विभाग का कार्यभार संभाला

मुंबई – मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। खड़गे इससे पहले सांस्कृतिक कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। इससे पहले, वे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं। राजस्व विभाग का कार्यभार संभालने के बाद, राजस्व मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले और अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे ने विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा के साथ-साथ आगे के कार्यों की योजना भी बनाई।

डॉ. केशव हेडगेवार के अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन

नागपुर – विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियाँ समय के साथ लुप्त हो गई हैं। फिर भी, भारतीय संस्कृति अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रह पाई है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण का अमूल्य कार्य संस्कृत भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। वास्तुकला, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान आदि क्षेत्रों का ज्ञान-भंडार संस्कृत भाषा में है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय इसे समाज तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वारंगा में पूज्य डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भवन का उद्घाटन और विद्यार्थी भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस अवसर पर सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटिल, वित्त राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल, कुलपति हरेराम त्रिपाठी,

संस्थापक कुलपति डॉ. पंकज चांदे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने भाषण में, मुख्यमंत्री फडणवीस ने संस्कृत भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉ. श्रीकांत जिचकर और पूर्व संस्थापक कुलपति डॉ. पंकज चांदे द्वारा दिए गए योगदान का गर्व से उल्लेख किया। चूँकि इस विश्वविद्यालय का नाम कवि-संस्कृतिविद् कालिदास के नाम पर रखा गया है, इसलिए प्रारंभिक अवधारणा इसे रामटेक में स्थापित करने की थी। हालाँकि, संस्कृत भाषा के इस ज्ञान केंद्र को वैश्विक स्तर तक पहुँचाने में आसानी हो, इसके लिए हमने इस संपूर्ण ज्ञान परिसर को वारंगा में विकसित करने का निर्णय लिया, जो रामटेक तालुका में एक शैक्षणिक परिसर के रूप में जाना जाता है और नागपुर के निकट है। उन्होंने कहा कि निकटवर्ती राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की तर्ज पर आने वाले समय में एक निश्चित समय-सीमा के भीतर यहाँ एक विश्वस्तरीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों और भारतीय जीवन पद्धति को उजागर करने और उनके मूल्यों को आम आदमी तक पहुँचाने में डॉ. हेडगेवार का योगदान अमूल्य है। ज्ञान की भाषा संस्कृत के ये मूल्य नई पीढ़ी तक पहुँचने चाहिए। यह हमारी ज्ञान की भाषा है। संस्कृत में शब्दों की संख्या 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख है। संस्कृत को दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा माना जाता है। उन्होंने कहा कि हम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से संस्कृत को और समृद्ध करेंगे। मैं संस्कृत भाषा सीखना चाहता हूँ। मेरी माँ संस्कृत में एम.ए. हैं और मैं भविष्य में इस विश्वविद्यालय की सेवा में अपना समय अवश्य लगाऊँगा, ऐसा उन्होंने आभार व्यक्त किया। आज के वैश्विक संदर्भ में, वैश्विक और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना एक ही है। वसुधैव कुटुम्बकम का आधार बहुत समृद्ध है। यदि हमें संस्कृत भाषा द्वारा प्रदत्त ज्ञान की शक्ति को समझना है, तो हमें उसके अर्थ को भी समझना होगा। इसके लिए भाषा आवश्यक है। यद्यपि संस्कृत भाषा के ग्रंथों और ऋचाओं के माध्यम से ज्ञान के अनेक भंडार अनेक घरों तक पहुँच चुके हैं, फिर भी संस्कृत भाषा को अब प्रजा के साथ-साथ राजाओं पर भी आश्रित होना चाहिए, ऐसा डॉ. भागवत ने कहा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण समय है। इसके लिए हमारा सत्व मूल्यवान है। आत्मनिर्भरता इसी सत्व पर निर्भर करती है। इसके लिए सामर्थ्य भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सामर्थ्य के पीछे मन, हृदय और बुद्धि स्वाभिमानी हों, तो वह सामर्थ्य और अधिक रचनात्मक हो जाता है। जहाँ सार और शक्ति है, वहाँ ऊर्जा है। ऊर्जा के साथ-साथ लक्ष्मी का भी अस्तित्व है, उन्होंने समृद्ध भारत की भूमिका समझाते हुए कहा।